Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of October, 2019.

An Agreement on Security Cooperation and a Memorandum of Understanding in the field of combating illicit trafficking and smuggling of narcotics drugs, psychotropic substances and chemical precursors between the Republic of India and the Kingdom of Saudi Arabia were signed on 29.10.2019 during the visit of Hon' ble Prime Minister of India to Saudi Arabia.

2. The Ministry of Home Affairs (MHA) and the National Disaster Management Authority (NDMA) organized a two-day workshop on sensitization of Nodal Officers for Disaster Management in Central Ministries/Departments, in New Delhi. Around 120 senior level officers attended the workshop from Ministries / Department of the Central Government, disaster management specialists, technical institutions and premium training institutes including NDMA, National Institute of Disaster Management and National Disaster Response Force.

3. During the month, advance release of Rs.1200 crore to the State Government of Karnataka, Rs.600 crores to the State Government of Maharashtra and Rs.400 crores to the State Government of Bihar was made from SDRF/NDRF.

4. On 14.10.2019, Union Home Secretary wrote letter to Chief Secretary, Maharashtra for taking necessary measures for incident free elections in the State.

5. An amount of Rs.34.59 crore was released to LWE affected States of Jharkhand and West Bengal as reimbursement under the Security Related Expenditure scheme. An amount of Rs.17.16 crore was released to CAPFs for carrying out various civic activities under the scheme of Civic Action Programme in LWE affected areas.

6. An advisory was issued to the State Government / CAPFs to sensitize them on activities of Left Wing Extremists in the LWE affected areas.

7. 72 Coys of CAPFs were deployed in various States viz. Telangana, Bihar, Jharkhand, Arunanchal Pradesh, Manipur, Uttar Pradesh, Delhi, and Punjab for maintaining law and order duty during Friday Prayers, Dusshera/ Durga Puja Festival, Chehallum Festival, Dipawali /Kalipuja, Chhath, Tawang Festival and Run for Unity etc .

8. On the recommendations of Election Commission of India, 777 Coys of CAPFs were deployed in connection with Election duties in Arunachal Pradesh, Uttar Pradesh, Tamilnadu, Odisha, Sikkim, Puducherry, Chhattisgarh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Meghalaya, Madhya Pradesh, Punjab, Bihar, Kerala, Assam, Gujarat, Telangana, Haryana, Maharashtra and Jharkhand.

9. An amount of Rs.160.59 crore has been sanctioned for development of infrastructure to the CAPF. An amount of Rs. 1.52 crore has been sanctioned as Ex-gratia Compensation to the NOKs of CAPFs in 7 cases.

10. On 31st October, 2019, 160 officials of various States Police/CAPFs/CPOs have been awarded "Union Home Minister's Special Operation Medal" for the year 2019.

11. During October, 2019, sanction for prosecution for filing the charge sheet against 38 accused persons was accorded under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and CrPC.

12. 25 posts in the National Human Rights Commission has been created during the month.

13. Rs. 155.37 crore has been released under the Umbrella Scheme for Modernization of Police forces during the month.

14. During the month more than 1695 kgs of Narcotics substances and Rs.28.32 lakhs have been seized. 47 persons including one foreign national were arrested for their involvement in drug trafficking.

15. During the month, an amount of Rs.46 crore was released to the State Government of Himachal Pradesh, Punjab and Uttarakhand under the Border Area Development Programme (BADP). The Total fund released under BADP during the current financial year (2019-20) as on 31.10.2019 is Rs.540.83 crore.

16. During the month, five State Bills were assented to by the Honble President of India. These are "The Orissa Ground Water (Regulation, Development & Management) Bill, 2011", "The Indian Stamp (Jharkhand Amendment) Bill, 2018", "The Gujarat Control of Terrorism and organized Crime Bill, 2015", "Industrial Dispute (Bihar Amendment) Bill, 2018" and "The Maharashtra Media Persons and Media Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property Bill, 2017".

*****

माह अक्तूबर, 2019 के लिए गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, उल्लेखनीय घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण गतिविधियां

भारत के माननीय प्रधानमंत्री की सउदी अरब की यात्रा के दौरान दिनांक 29.10.2019 को भारत गणराज्य और किंगडम ऑफ सउदी अरबिया के बीच पूर्ववर्तियों द्वारा अवैध ट्रैफिकिंग और स्वापक औषध तथा मन प्रभावी: पदार्थ और रसायनों की तस्करी से निपटने के क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग संबंधी करार और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2. गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली के केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में आपदा प्रबंधन के प्रति नोडल अधिकारियों को संवेदनशील बनाए जाने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सहित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों से लगभग 120 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

3. इस माह के दौरान राज्य आपदा मोचन बल/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से केरल राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपये तथा बिहार राज्य सरकार को 400 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की गई।

4. केन्द्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र को राज्य में घटना मुक्त चुनाव कराए जाने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए दिनांक 14.10.2019 को पत्र लिखा।

5. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्य झारखण्ड और पश्चिम बंगाल को सुरक्षा संबंधी व्यय की स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में 34.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्य कार्यक्रम की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न नागरिक कार्यकलापों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय शस्त्र पुलिस बलों को 17.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई।

7. कानून और व्यवस्था बनाए रखने, शुक्रवार की नमाज, दशहरा/दुर्गापूजा महोत्सव, चेहल्लुम समारोह, दीपावली/कालीपूजा, छठ, तवांग समारोह और एकता दौड़ आदि के दौरान डयूटी करने के लिए विभिन्न राज्यों अर्थात तेलंगाना, बिहार, झारखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 72 कंपनियां तैनात की गईं।

8. भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, सिक्किम, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, केरल, असम, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखण्ड में निर्वाचन ड्यूटी के संबंध में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 777 कंपनियां तैनात की गई।

9. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए अवसंरचना विकसित करने हेतु 160.59 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है। 07 मामलों में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निकटतम सगे-संबंधियों को अनुग्रही प्रतिपूर्ति के रूप में 1.52 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

10. वर्ष 2019 के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों को 31 अक्तूबर, 2019 को केन्द्रीय गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक प्रदान किया गया है।

11. अक्तूबर, 2019 के दौरान, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 तथा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 38 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की संस्वीकृति प्रदान की गई।

12. इस माह के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 25 पद सृजित किए गए हैं।

13. इस माह के दौरान, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत 155.37 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

14. इस माह के दौरान, 1695 किलोग्राम से अधिक स्वापक पदार्थ तथा 28.32 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। एक विदेशी राष्ट्रिक सहित 47 व्यक्तियों को ड्रग ट्रैफिकिंग में उनके संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

15. इस माह के दौरान, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखण्ड राज्य सरकारों को 46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 540.83 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है।

16. इस माह के दौरान, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पांच राज्य विषयक विधेयकों को अनुमति प्रदान की गई है। ये विधेयक "उड़ीसा भूजल (विनियमन, विकास प्रबंधन) विधेयक, 2011, "भारतीय स्टांप (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018, "गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2015, "औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018" और "महाराष्ट्र मीडिया परसन तथा मीडिया संस्थान (हिंसा और क्षति निवारण या संपत्ति की हानि विधेयक, 2017) हैं।"

*****